[Shri Ghulam Rasool Matto]

are able to function properly or not? If they function are they being molested by the police? We are finding that the police are resorting to unnecessary excesses. I want the Honourable Home Minister to enlighten us about these incidents. Thank you.

REFERENCE TO THE DAMAGED THE RECENT HAILSTORMS IN SOME PARTS OF MADHYA PRADESH

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से आधे से ज्यादा जिलों में अति ओलावृष्टि हुई है और जिससे किसान जो कि साल भर से फसल की तैयारी कर रहा था वह बर्बाद हो गया है। हमारे गांवों में एक कहावत है :

"हरी खेती गाभिन गाय ।
मुंह पड़े तब जानी जाय" ।

किसान के साथ यही हो रहा है। दुर्भाग्य तो यह है कि दैवी आपदाओं पर पिछले सप्ताह में महाराष्ट्र में ओलावृष्टि के बारे में धावे साहब ने सवाल उठाया था आज सदन में भी देश के कुछ हिस्सों में सूखा पर चर्चा हुई बाढ़ पर बिहार और यू०पी० की चर्चा हुई कल लोक सभा में भी दैवी आपदाओं पर किसान को चर्चा हुई। यह जो 22 से ज्यादा जिले हैं उनमें यह शहडोल जिला ऐसा है जिसमें चार बार ओलावृष्टि हुई है फसल तहस-नहस कर दी गई आधा किलो वजन के ओले पड़े, सीधी का एक जिला है उस जिले में भी भयंकर ओलावृष्टि हुई है। बिलासपुर संभाग में कई जिले आते हैं वहां ओलावृष्टि हुई है। सरगूजा का जिला है मंडला का जिला है जबलपुर सम्भाग में अनेक जिले आते हैं इंदौर में अनेक जिले आते हैं उज्जैन का सम्भाग है वहां गुना और ग्वालियर में ये 45 में आधे से ज्यादा जिले हैं जहां पर कि ओलावृष्टि हुई जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जहां तक वसूली का सवाल है आजकल खेती व्यापारिक दृष्टि से हो रही है। मंहगा खाद है मंहगी सिंचाई के साधन हैं, मंहगी बिजली की दरें हैं, मंहगे बीज हैं और मेहनत और मजदूरी भी मंहगी हो गई है, इसके कारण साधारण किसान तो एक तरह से चौपट हो गया है। मैं केन्द्रीय सरकार से चाहूंगा कि वह राज्य सरकार से मिल कर जहां भी किसान की जितनी वसूलियां हैं चाहे सहकारी समितियों के कर्जे हैं चाहे बैंकों के ऋण हैं ऐसी सभी वसूलियां बन्द होनी चाहिये। उपसभाध्यक्ष महोदय पशुधन की भी बहुत बड़ी हानि हुई है और पशुधन के साथ-साथ फसलों का भी जो नुकसान हुआ है तो उसके लिये राहत कार्य तेज किये जायें तभी किसानों की एक तरह से दिलजोई हो सकेगी। उसका घाटा तो पूरा नहीं हो सकता लेकिन है 20–22 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार को वहां भेजना चाहिये और राज्य सरकार से भी कहना चाहिये। इससे किसानों की क्षति पूर्ति तो नहीं हो सकेगी लेकिन उनकी भयानक रूप से तमाम फसल जो बरबाद हो गई है जो उनकी आशा थी निराशा में बदल गयी है। उसके लिये सरकार अधिक से अधिक सहायता करे। मैं यही चाहूंगा केन्द्रीय सरकार से। हमारे दलबीर सिंह के इलाके का जहां तक सवाल है हमारे राज्य मंत्री रेलवे श्री माधव राव सिंधिया जी के इलाके का सवाल है; और जो अनेक इलाके हैं मध्य प्रदेश के जहां भयंकर ओला-वृष्टि हुई है और किसान बरबाद हुये है, उनके लिये ज्यादा से ज्यादा मदद करें, राज्य सरकार की तरफ से करें और केन्द्र सरकार की तरफ से भी कर सकें तो वही अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक उनकी सहायता की जाय।

REGARDING REPORTED RESIGNATION OF GOVERNMENT HEADED BY SHRI G. M. SHAH IN JAMMU AND KASHMIR.

उपसभाध्यक्ष (श्री एम० पी० कौशिक) केसरी जी स्टेटमेंट है क्या ?

संसदीय कार्य (राज्य सभा) विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी): स्टेटमेंट तो नहीं हो सकेगा, सर।

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Advani. One minute.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, आज प्रातःकाल मैंने सभापति जी से अनुमति ली थी, इस कारण ली थी कि जम्मू-काश्मीर में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से वहां के मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री बने हुये थे और कांग्रेस पार्टी के समर्थन वापस लेते ही वहां की सरकार अल्पमत में आ गई और इस तरह वहां पर वह पद पर बने रहने के अधिकारी नहीं रहे। स्वाभाविक है कि इस संवैधानिक संकट के लिये केन्द्रीय सरकार में चिंतन होता रहे। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि प्रातःकाल भी संसद् के होते हुये भी इस मामले में संसद् को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। अभी भी जितनी जानकारी मुझे है, वह टेलीप्रिंटर के माध्यम से है, जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने सुबह कह दिया कि यू०एन०आई० और पी०टी०आई० का टेलीप्रिंटर पर क्या आता है, उसके आधार पर परमीशिबल नहीं हो सकता। यह बात मैं मानता हूं। इसलिये हम अधिकृत रूप से इनसे बयान चाहते थे और ताज्जुब इस बात का है कि साढ़े पांच बजे जाने के बाद भी संसद् को विश्वास में लिया नहीं गया।

अब मैं अपनी राय प्रकट करना चाहता हूं बावजूद इसके कि इस वक्त मेरे पास दोनों संविधान हैं--भारत का संविधान और जम्मू-काश्मीर का संविधान। दोनों विकल्प सरकार के सामने। मैं यह नहीं जानता हूं कि क्या करने वाले हैं? एक विकल्प है जम्मू-काश्मीर के संविधान के अन्तर्गत और अनुच्छेद 92 के अन्तर्गत वहां पर गवर्नर रूल लागू करें, राज्यपाल का शासन वहां पर किया जाय, जो केंद्रीय सरकार के हाथ में ही है, उनके हाथ में नहीं है। आर्टिकल 92, सब-क्लाज 5 जम्मू-काश्मीर का संविधान कहता है कि :

"No proclamation under sub-section (1)'—which refers to the breakdown of the Constitutional machinery—' shall be issued except with the concurrence of the President of India."

अब लगता यह है कि प्रोसेस तो शुरू कर दिया, प्रोसेस उन्होंने कल रात ही शुरू कर दिया और चिट्ठी लिखकर भी भेज दी गवर्नर को कि हम विदड्रा करते हैं। लेकिन उस पर ख्याल करते रहे कि इसे 92 में करें या आर्टिकल 356 में करें। कहते हैं कि मीटिंग केबिनट की अभी चल रही है, शायद हो सकता है, मैं नहीं जानता...

This is the way in which the whole Government functions.

आखिर तक पता नहीं लगता कि करना क्या है और इतना कुछ हो जाता है कि फिर बदलते रहते हैं, चाहे वह प्राइमेस हो या मुस्लिम-ला हो या और कुछ हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में काश्मीर की परिस्थितियां आज क्यों पैदा हुई, इस पर विचार करना चाहिये और इस संवैधानिक संकट का कानूनी तौर पर जैसे मुकाबला करना चाहिये, आर्टिकल 92 में किया जाये या फिर आर्टिकल 356 आफ दी इंडियन कान्स्टीट्यूशन में किया जाये। ये बिल्कुल आवश्यक बातें हैं और उसके आधार पर हम मांग करते रहे हैं सारे विपक्षी लोग। संसद् का अधिवेशन शुरू होने के पहले ही दिन सारे विपक्ष ने यह मांग की कि जी०एम०शाह की सरकार को बर्खास्त किया जाये वहां की असेम्बली को डिजोल्व किया जाये और वहां की जनता को अपनी नयी असेम्बली और नयी सरकार चुनने का विकल्प दिया जाये।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि वहां पर शाह साहब का रेजिगनेशन मांगा गया और शाह साहब ने रिजाइन कर दिया हैं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं और खुशी प्रकट करता हूं। आगे सरकार क्या करेगी, उसको देखूंगा और उसके बाद अपनी टिप्पणी करूंगा। लेकिन मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं, वह यह कि परिस्थिति क्यों पैदा हुई? परिस्थिति इसलिये पैदा हुई कि जो आरोप लगाकर के आपने पहले फारुख अब्दुल्ला साहब की सरकार को हटाया था। सार्वजनिक रूप से वह बात नहीं थी। सार्वजनिक

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

रूप से बात यह थी कि कुछ लोगों ने उनका जब साथ छोड दिया था, तो उनकी अल्पमत में सरकार हो गयी, इसलिये उनको हटाया गया । लेकिन उसके बाद दुनियां भर के आरोप उन पर लगायें कि वे राष्ट्र-विरोधी तत्वों के साथ मिले हुये हैं, राष्ट्र-विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देते रहते हैं । मेरा आरोप है कि जी०एम० शाह की सरकार राष्ट्र-विरोधी तत्वों को बहुत बढ़ावा देती रही, इतना बढ़ावा देती रही कि पहली बार पिछले दो-तीन सप्ताह में न केवल काश्मीर वैली में बल्कि जम्मू तक में हमने भारत विरोधी नारे सुने, पाकिस्तान जिन्दाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे सुने । यह जी एम० शाह की सरकार आप पर टिकी थी । वह एक दिन नहीं टिक सकती थी । मुझे ताज्जूब है कि इतने दिन उसे क्यों चलने दिया । इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले चार सप्ताहों में काश्मीर वैली में, विशेषकर अनन्तनाग डिस्ट्रिक्ट में मन्दिर तबाह किए गए, कम से कम 50 मन्दिर तबाह हो गए, रेज्ड टु दी ग्राउन्ड, आग लगा दी । यह बात अलग है कि हिन्दुस्तान की प्रकृति ऐसी है कि हम इसके कारण कभी भी सांप्रदायिक विद्वेष नहीं पैदा होने देंगे । हम इसका आरोप किसी एक सम्प्रदाय पर नहीं लगाते । मेरा आरोप सरकार पर है, आप पर है जिन्होंने उस सरकार को बनाए रखा इतने दिनों तक । मैं चाहता हूं कि उस परिस्थिति का निरीक्षण किया जाये । वहां मन्दिर ध्वस्त किए गए, लोगों पर हिंसा की गई और उसके परिणामस्वरूप यह हुआ कि वहां बसने वाले अल्पसंख्यक इस स्थिति में आ गये कि जब वहां हमारे अश्विनी कुमार और दूसरे लोग गये तो वे कहने लगे कि हमको यहां से निकालो । बंजर जमीन दे दो । हम वहां जाकर बस जायेंगे, हम यहां नहीं रहेंगे । यह फीलिंग अल्पसंख्यक हिन्दुओं के मन में इस सरकार ने पैदा होने दी । यह इतनी बड़ी चिन्ता की बात है कि उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे । इस लिये मैं सरकार से इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक संवैधानिक संकट है उसका अवश्य निराकरण करिये । जी० एम० शाह की सरकार हट गई । मैं चाहूंगा कि यह अन्तरिम काल कम से कम हो, जल्दी से जल्दी वहां की जनता को चुनाव कराने का अधिकार मिले । मैं जानता हूं कि गवर्नर रूल का अन्त 6 महीने में कर चुनाव कराना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल हुआ तो शायद तीन साल की अवधि मिल जायेगी । यही कारण है कि अभी निर्णय नहीं हुआ । सवेरे गवर्नरस रूल की बात हो रही है, अब शायद किसी ने कह दिया कि प्रेसिडेंट रूल से तीन साल की अवधि मिल सकती है । मैं उससे कम सम्बन्धित हूं । मैं इससे ज्यादा सम्बन्धित हूं कि इस बात को तुरन्त आवश्यकता है कि वहां जो मन्दिर ध्वस्त किए गए उनको फिर से खड़ा किया जाये, वहां जो माइनारिटीज में अविश्वास पैदा हुआ उसको दूर किया जाये । मेरी शिकायत है इस सरकार से कि वहां चीफ मिनिस्टर गया नहीं । गवर्नर से शिकायत है कि उसको भी वहां जाने में 20 दिन लगे । इसलिये मैं केसरी जी के माध्यम से अपील करना चाहता हूं प्रधान मंत्री से कि वे वहां जायें, तुरन्त काश्मीर वैली में जाये । अच्छा होगा कि संसद की आल-पार्टी टीम जाये । सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि वहां की माइनारिटीज में विश्वास पैदा हो, हम लोग हैं, देश आपके साथ है, यह आश्वस्ति उनके मन में पैदा करने की आवश्यकता है । मैं चाहता था कि गृह मंत्री इस समय आकर अपना बयान देते, हमको विश्वास में लेते, उसके बाद ये बातें कहता । वह नहीं हुआ । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ विचार प्रकट करने का मौका दिया ।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, in the morning we raised that issue. As my colleague has said, it is very serious that important events occur without our knowledge outside Parliament and they are not reported to us. My colleague, Mr. Advani, has commented on this. The main culprit for the present situation in Jammu and Kashmir is not G. M. Shah, it is not the MLAs; who defected and formed the Government with the support of the Congress; the main culprit, the real culprit, is the Congress

Party which propped up the most undesirable element in Jammu and Kashmir.

Sir, during these few months, what Mr. G. M. Shah and his Government have done is to convert a seemingly secular State into a theocratic State. At no time in the past such atrocities were committed. As my colleague pointed out, innocent people were tortured, were harassed and were murdered and temples were burnt down and they were desecrated and life in J & K valley became intolerable.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Your time is over now.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I am not taking much of your time.

Sir, the Government of Mr. G. M. Shah was a big disaster which was sustained by the Congress (I) Party alone. May I say...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Sir, I want a clarification. It is all right that you permitted Mr. Advani to speak. That does not mean that all the Members will start speaking on this. (*Interruptions*). I can understand if they ask for clarifications after the Minister makes the statement. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: (West Bengal): We have to speak. (*Interruptions*).

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): This is an important matter and we have to speak. (*Interruptions*).

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Under what procedure? (*Interruptions*). Under what procedure? (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: This morning the Chairman has said that a statement would be made. But the statement was not made and we protested against that. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): All of you, please sit down. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The statement has not been made .(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. KAUSHIK): All of you, please sit down. In the morning, the Chairman had given permission to Mr. Advani to speak if there was no statement. He had said that if there was no statement, he would be given a chance to speak for two minutes. But I have given him more than five minutes. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is not a question of any personal privilege. (*Interruptions*). It is a question of this Parliament, it is a question of the Rajya Sabha, discussing a very important matter. (*Interruptions*). You have stopped this House from discussing a very important matter. It is a contempt of parliamentary democracy itself. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. KAUSHIK): You can discuss it with the Chairman on Monday. He never gave permission to all. (*Interruptions*).

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Sir, I want to put the record straight (*Interruptions*). Sir, I want to put the record straight. In the morning, the Chairman was good enough to say, in response to my intervention, that in the evening or around 5 o'clock, the Government would make a statement. Then we kept quiet. Anyway, even now it is not too late. The Government can come and make a statement and we will sit down and we will ask for clarifications later on. But I would like to make it very clear that Parliament is being bypassed everyday. We have been pointing out that Parliament is being bypassed even in matters which are vital, with which we are vitally concerned. This is one instance where we are very much exercised and no opportunity was given to us to seek clarifications or even to discuss. What shall we do now? You please tell us as the Vice-Chairman of this House. This is an important development and a very serious development and all of us are concerned. And, Sir, it is not a question of this party or that party. They are also concerned about it and this is a very important deve-

[Shri M. S. Gurupadaswamy]

lopment where a certain decision has been taken by the Govenment and we as Members of Parliament have got very right to know the stand of the Government in this matter. Therefore, Sir, I would beg of you,.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. KAUSHIK): The Government has not announced anything. (*Interruptions*).

SHRI LAL K. ADVANI: What do you do then? (*Interruptions*).

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Everybody knows about this and the whole world knows about what is happening except this Parliament. (*Interruptions*). Everybody knows it and the whole world knows about what is happening. Only Parliament does not know. (*Interruptions*).

SHRI SITARAM KESRI: Mr. Gurupadaswamy, I am not stopping you. (*Interruptions*).

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I have not yielded and I am not yielding. (*Interruptions*). I have not yielded. Please sit down. (*Interruptions*). I have not yielded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): You please hear him first. (*Interruptions*). You kindly hear what he says.

श्री सीताराम केसरी : आई एम नाट स्टापिंग यू । ऐसा मत समझिये । देखिये, चेयरमैन साहब ने जिस समय कहा था तो उन्होंने यह भी कहा था कि अगर स्टेटमेंट नहीं होगा तो आडवाणी साहब बोलेंगे ... (**व्यवधान**)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is a question of privilege. (*Interruptions*)

श्री सीताराम केसरी : मेरी बात सुन लीजिए । जो बात हुई है मैं उससे गिडिगता नहीं हूं । जब स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो आडवाणी साहब ने सारी भावनाओं को व्यक्त कर दिया । जब स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो इसके पीछे कोई बात है । यह तो नहीं है कि आपके प्रति असम्मान है गवर्नमेंट का । यह कहना कि सदन के प्रति सरकार का सम्मान नहीं है, गलत है । किसी वजह से मान लीजिये । ... (**व्यवधान**)। मैं इतना ही कह रहा हूं कि यह इश्यू बड़ा सेंसिटिव है । आडवाणी साहब ने सारी बातें व्यक्त कर दी, उसके बाद भी अगर आप सोचते है तो सोचिये । लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि सरकार स्टेटमेंट नहीं दे रही है तो कोई वजह होगी । उसके बाद जब समय आएगा तो बात आपके सामने आ जाएगी ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is a question of privilege.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): There is no issue.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Prime Minister has asked the Chief Minister to resign.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: We would like to know whether the Government is prepared to take the House into confidence. We should not be bypassed What are we here for

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Since the Government is not making any statement so far, I adjourn the House till Monday, 11 A.M.

The House then adjourned at fifty-three minutes past five of the clock. till eleven of the clock on Monday, the 10th March, 1986.